THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) The Report of the Central Advisory Board of Education (CABE) Committee on Policy (Janardhana Reddy Committee was considered by the CABE in its meeting held on 5th and 6th May, 1992. On the basis of the recommendations of the CABE certain modifications were effected in the National Policy on Education (NPE), 1986. The revised Policy Formulations were laid on the table of the House on 7th May, 1992.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

316. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक कब तक पुनःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने मई, 1990 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 को संशोधित करने के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूपण समिति गठित की थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुरोध पर प्रारूपण समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को उसके विचारार्थ भेजी गई थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित करने के लिए कानून तैयार करने के संबंध में आगे की कार्रवाई कार्यकारी परिषद् के विचार उपलब्ध होने के पश्चात् ही संभव हो सकेगी।

मध्य प्रदेश को रियायती दर पर कागज की आपूर्ति

317. **श्री लखीराम अग्रवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के मुद्रण के लिये रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराये जाने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षिक क्षेत्र को मुद्रण का सफेद कागज, रियायती दरों पर दिए जाने की एक योजना, 31 मार्च, 1990 तक चल रही थी। मार्च, 1990 में, इस योजना को समाप्त कर दिये जाने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए रियायती दरों पर मुद्रण का सफेद कागज उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस योजना को बंद कर दिए जाने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य को कागज आवंटित नहीं किया जा सका।

देश में नवोदय विद्यालय

318. **श्री राम जेठमलानी :**

श्री रणजीत सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 28 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 624 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1986 में घोषित शिक्षा नीति के अन्तर्गत देश में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है ;

(ख) यदि हां, तो देश में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) गत शैक्षणिक सत्र में देश में स्थापित किये गये नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी; और

(घ) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में इन विद्यालयों की स्थापना के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) नवोदय विद्यालयों की योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय-विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(ग) 19 (उन्नीस)

(घ) फिलहाल, सरकार का उद्देश्य, सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से अपेक्षित सुविधाओं सहित उपयुक्त प्रस्तावों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, अगले तीन वर्षों के दौरान, यदि सम्भव हो, देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने का है।

शिक्षा संबंधी लक्ष्य प्राप्त किया जाना

319. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **मानव ससाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "यूनेस्को अजेंस इंडिया टू मीट एजूकेशन टार्गेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यूनेस्को के महानिदेशक और युनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने एक संयुक्त पत्र में शिक्षा के प्रसार और संवर्धन का लक्ष्य प्राप्त करके देश के विकास (आर्थिक तथा सामाजिक) की गति तेज करने का सरकार से आग्रह किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी हाल ही में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए जबकि इस समय इस पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3.6% खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस शीर्ष के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) मे उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :(क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को के महानिदेशक और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक ने भारत सहित लगभग दर्जन विकासशील देशों के शासनाध्यक्षों को संयुक्त पत्र लिखे हैं, जिसमें उनसे अपने-अपने देश में और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से शिक्षा की सफलता के सभी उपाय सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत सहयोग प्रदान करने और अपने आपको संबद्ध करने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि विशेषरूप से भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 5 तथा 6 मई, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 47वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि शिक्षा के परिव्यय में राष्ट्रीय आय के 6% तक वृद्धि की जानी चाहिए।